उत्तर प्रदेश में निवेश बना 'विशेष'

Anand.Tripathi@timesgroup.com

लखनऊः उद्योग और निवेश की सबसे अहम शर्त है बुनियादी संसाधन, भरोसा और सहूलियत। इन शर्तों के आलोक में कुछ ताजा रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त में आई रिपोर्ट कहती है कि 2013-14 में बैंकों से लोन के लिए देश में जितने प्रॉजेक्ट स्वीकृत हुए थे, उनमें यूपी की भागीदारी महज 1.1% थी। 2022- 23 में यह भागीदारी बढ़कर 16.4% हो चुकी है, यह देश में सबसे अधिक है। अगर इन आंकड़ों के आर्थिक आकार को देखें तो एक दशक में इनमें चार गुना बढ़ोतरी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी उत्तर प्रदेश से पीछे छूट गए हैं। छह साल में यूपी में बैंकों में जमा हुए पैसों के मुकाबले कर्ज देने का अनुपात भी छह फीसदी बढ़ा है। बैंकिंग संस्थाओं के भरोसे की मजबूत हुई बुनियाद पिछले कुछ वर्षों में यूपी के निवेश के लिए विशेष बनने की कहानी कहती है।

बाजार का पूरा विस्तार 'परसेप्शन' पर टिका होता है। देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री हब बनने के सपने और उससे हकीकत की ओर बढ़ने की यात्रा भी इससे होकर गुजरती है। इस दशक में यूपी में बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने की कोशिशों पर काम हुआ। कनेक्टिविटी ने जब पश्चिम से पूरब और शहर से सुदूर के सफर को सहज बनाया तो निवेशकों को भी यूपी में उम्मीद दिखने लगी। उनकी 'असहजता' और हिचक की आखिरी दीवार सुरक्षा और भरोसे की थी। हिचक की यह दीवार भी राजनीतिक स्थिरता व नीतिगत निर्णयों ने तोड़ दी है।

ऐसे जमे पांव

राजधानी लखनऊ के बगल के जिले हरदोई में संडीला अपने लड्डुओं के स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन औद्योगिक मानचित्र में अब इसकी अलग तस्वीर है। इंग्लैंड की मशहूर गन निर्माता कंपनी वेब्ले एंड स्कॉट ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत चार साल पहले यहां सियाल ग्रुप के साथ इकाई खोलने का फैसला किया। देश में अपनी पहली यूनिट खोलने के लिए मशहूर विदेशी कंपनी ने दिल्ली से करीब सवा चार सौ किमी दूर यूपी के इस औद्योगिक कस्बे को चुना। यहां रिवॉल्वर का निर्माण व बिक्री शुरू हो चुकी है। यूपी में निवेश के समावेशी होते परिवेश का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। नामी बेवरेज कंपनी पेप्सिको के मथुरा प्लांट में इसी साल अप्रैल से चिप्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। गोरखपुर में इसकी एक और यूनिट का काम जारी है, जहां सॉफ्ट ड्रिंक व मिल्क बेस्ड ड्रिंक तैयार किए जाएंगे। यूपी के छोटे शहरों में उभर रही संभावनाओं व निवेश के परिदृश्य की गवाही इसी साल फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आंकड़े भी देते हैं। समिट में पूर्वांचल के लिए 7.80 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो कुल प्रस्तावों का लगभग 23% है। बुंदेलखंड में 3.72 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर सहमति बनी है। ये वे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा आर्थिक पिछड़ेपन व त्रासदी की घटनाओं के कारण होती थी। अब इनका कलेवर बदल रहा है।

मूल पहचान को संजीवनी

यूपी में निवेश व इंडस्ट्री की बढ़ी पैठ ने रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है। वाराणसी के रहने वाले हिमांशु निषाद बताते हैं कि बीटेक करने के बाद उन्होंने पुणे का रुख किया। वहां एक कंपनी में करीब 12 साल तक नौकरी की। 2018 में हिमांशु को पता लगा कि सोलर सेक्टर की एक कंपनी पूर्वांचल और बुंदेलखंड में प्लांट लगा रही है। हिमांशु ने नौकरी के लिए अप्लाई किया और उनको लखनऊ में ही काम मिल गया। कार्यस्थल से उनके घर की दूरी लगभग 1500 किमी से कम होकर 300 किमी रह गई है। झांसी के कुलदीप ने 2007 में एमबीए किया था। 10 साल दिल्ली में नौकरी की। उनके शहर में एग्रोटेक की एक कंपनी खुली और कुलदीप अपने घर में रोजगार पाने में सफल रहे हैं। दरअसल, यूपी की आर्थिक व रोजगार की संभावनाएं बड़े उद्योगों के साथ ही इसकी मूल पहचान में समाहित है। हर जिला अलग-अलग परंपरागत उत्पादों की विशेषज्ञता लिए हुए है और उसके जरिए रोजगार की गारंटी भी। पिछले छह साल में नीति नियंताओं ने यूपी की मूल पहचान को संजीवनी देकर इसे औद्योगिक ताकत के रूप में उभारने की दिशा में काम किया। यूपी के स्थापना दिवस पर 2018 में लॉन्च हुई 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट' योजना ने यूपी के एमएसएमई बेस को एक नया स्वरूप दिया। हुनर को सरकारी प्रयासों का साथ मिला तो वे चमक उठे। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2013 में प्रदेश में 44.03 लाख एमएसएमई इंडस्ट्री थी, जिससे 92.26 लाख लोगों को रोजगार मिला था। एक दशक में यह संख्या दोगुनी हो गई है। इस समय में प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई हैं। सरकार का दावा है कि इससे 1.70 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं।

दोगुनी बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

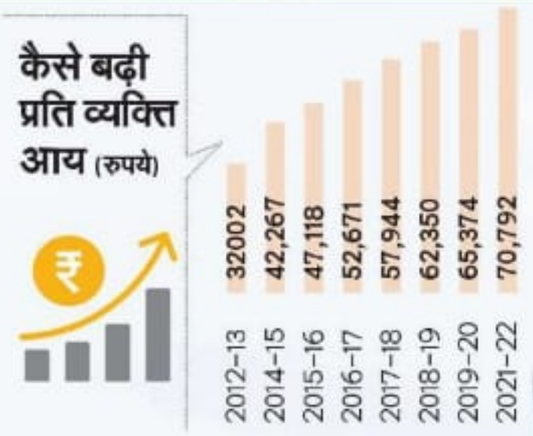

किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की का पैमाना वहां की प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रदेश में जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर भी इसका असर देखने को मिला है। पिछले एक दशक में यूपी में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। राज्य नियोजन संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 32,002 रुपये थी, जो 2021-22 में बढ़कर 70,792 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। 2014-15 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 42,267 रुपये था। वहीं 2015-16 में यह आंकड़ा 47,118 रुपये हो गया। 2017-18 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 57,944 रुपये थी, जो कोरोना काल के दौरान 61,374 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई थी। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 70,792 रुपये हो गई है।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब

2013-14 में जब देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक इमर्जिंग सेक्टर के रूप में उभर रहा था तब यूपी ने पहली बार पॉलिसी बनाकर दक्षिण कोरिया और ताइवान की कई कंपनियों को प्रदेश बुलाया। 2016 में दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी सैमसंग ने प्रदेश में 1970 करोड़ रुपये का निवेश किया। 2017 में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष क्षेत्र चिह्नित किए गए। इस दौरान अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का लाभ भी यूपी को खूब मिला। इस दौरान चीन की मोबाइल कंपनी वीवो ने प्रदेश में 7000 करोड़ रुपये का निवेश किया। वहीं ओप्पो ने 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर ग्रेटर नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। मोबाइल इक्यूपमेंट बनाने वाली कई कंपनियों ने भी निवेश किया। मोबाइल के लिए लीथियम बैट्री बनाने वाली चीन की कंपनी सनवोडा ने ग्रेटर नोएडा में 1500 करोड़ रुपये का निवेश कर प्लांट लगाया। इन निवेशों का नतीजा है कि देश में बनने वाले कुल मोबाइल का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा अकेले यूपी में बनता है।

> अलग-अलग सेक्टर में व्यवस्थित रूप से किए गए सरकार के प्रयासों के परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश देश-दुनिया में निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन चुका है। यूपी देश में सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य है। प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, नागरिकों के समक्ष पहचान का संकट नहीं है।
>
> -योगी आदित्यनाथ, सीएम, यूपी

इमर्जिंग सेक्टर में भी पैठ

यूपी नई संभावनाओं को टटोल रहा है। कोरोना काल के दौरान हीरानंदानी ग्रुप ने प्रदेश में पहला डेटा सेंटर बनाने का फैसला लिया। तब प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 250 मेगावॉट क्षमता के डेटा सेंटर लगाए जाएंगे। मगर नई डेटा सेंटर पॉलिसी आने के महज कुछ ही महीनों में राज्य सरकार को 7 नए डेटा सेंटर बनाने के प्रस्ताव मिले, जिनकी क्षमता 900 मेगावॉट थी। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क 2022 में ऑपरेशनल हो गया है। इस सेक्टर में अडाणी, सिफी जैसी कंपनियां डेटा सेंटर बना रही हैं। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को इलेक्ट्रिकल वीइकल क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हिन्दुजा ग्रुप प्रदेश में 1000 करोड़ रुपये का निवेश ईवी सेक्टर में करने की तैयारी कर रहा है।

सार्वजनिक निवेश बढ़ा

2018 में हुए इंवेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान किया था। डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है। 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा झांसी में भारत डायनेमिक्स प्लांट लगाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के तहत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में 6 नोड बनाए गए हैं। अब तक इन सभी नोड्स में अरबों रुपये के निवेश प्रस्ताव यूपीडा को मिल चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान डिफेंस सेक्टर में 61,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जिससे 28,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फरवरी, 2020 में राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था।

सरकार ने थामा निवेशकों का हाथ

यूपी में निवेश की बदली तस्वीर व उद्योगों की बढ़ी आमद की पीछे बड़ी वजह सरकारी काम-काज के ढर्रे में आया बदलाव भी है। नीति नियंताओं ने यह बखूबी समझा कि यूपी की औद्योगिक संभावनाओं को परिणाम तक ले जाना है तो उसके लिए परिमाण भी बदलने होंगे। पिछले छह दशक में नीतियों में किए गए व्यापक बदलाव, सुरक्षा के परिवेश इसी सोच के जमीनी अमल की नजीर हैं। यही वजह रही है कि यूपी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में अपनी रैंकिंग कई गुना सुधारने में सफल रहा। इसने देश ही नहीं विदेश के निवेशकों का ध्यान भी यूपी के ओर खींचा है। कोविड काल में जब दुनियाभर की कई कंपनियां चीन से पलायन कर रही थीं, तो यूपी उनके लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा। इस दौरान चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही कई कंपनियों ने यूपी की ओर रुख किया। विभागों में निवेशकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

इन्फ्रा से बदली तस्वीर

उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच साल में सड़क, बिजली, पानी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी काम किया है। आज प्रदेश के पास सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो तीन इंटरनैशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। जेवर और अयोध्या के हवाईअड्डे पर काम चल रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी होने से अब इंडस्ट्री एनसीआर रीजन के साथ-साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी लग रही हैं। उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी जितनी जरूरी है, उतनी ही बिजली की उपलब्धता। शहरों और इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कुल जीडीपी में 8 प्रतिशत की भागीदारी है। पांच साल में प्रति व्यक्ति आय 23 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। 24 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में 56 प्रतिशत लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर आया था। निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल ने निवेशकों की दिक्कतें काफी कम की हैं।

प्रो. हिमांशु राय, डायरेक्टर IIM इंदौर

ग्रीन इंडस्ट्री, टूरिज्म, ओडीओपी पर फोकस करे सरकार

विकास की रफ्तार और तेज करने के लिए सरकार को ग्रीन इंडस्ट्री मसलन इलेक्ट्रिक वीइकल, सोलर एनर्जी पर काम करना चाहिए। साथ ही इन इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नॉलजिकल असिस्टेंस पर काम किया जाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा सकती है। प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास के ईकोसिस्टम को तैयार किया जाए। ओडीओपी प्रॉडक्ट्स के कारीगरों की ट्रेनिंग, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग पर काम होना चाहिए।